दुर्गा बर्मन (रॉय)

बनाम

सिक्किम राज्य

(2004 की आपराधिक अपील संख्या 1010)

31 जुलाई 2014

[मदन बी. लोकुर और कुरियन जोसेफ, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860 एसएस.302, 380 आर/डब्ल्यू एस। 34 हत्या – बंधन से गला घोंटने के कारण हुई - मृतक के घर से कलाई घड़ी चोरी हो गई, मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर स्थापित किया गया, अपीलकर्ता सहित दो आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया - उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखा, लेकिन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। अपील, आयोजित: अभियोजन पक्ष प्रभावी अभियोजन के लिए नींव रखने में विफल रहा और यह संदेह से परे साबित नहीं हुआ कि अपीलकर्ता ने हत्या की थी - यह पर्याप्त नहीं है कि परिस्थितियाँ आरोपी की संलिप्तता की संभावना या संभाव्यता पैदा करती हैं; परिस्थितियों में सभी उंगलियाँ केवल अभियुक्त और अभियुक्त पर ही उठनी चाहिए, इस मामले में ऐसी स्थिति नहीं थी - शृंखला भी पूरी नहीं थी - अन्य अभियुक्त, जो अभियोजन पक्ष के अनुसार आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध का अपराधी था , उच्च न्यायालय द्वारा बरी

कर दिया गया था - राज्य ने बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर नहीं की - अपीलकर्ता के खिलाफ एकमात्र साक्ष्य अपीलकर्ता की मां से और उसके माध्यम से पीडब्लू 1 की कलाई घड़ी की बरामदगी थी - उसकी जांच नहीं की गई थी - अपीलकर्ता की उपलब्धता के बावजूद, उसकी मां के माध्यम से वसूली कैसे की गई, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं - वसूली में लगभग दस दिनों की देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं, गवाहों ने प्रकटीकरण बयान या जब्ती का समर्थन नहीं किया - कलाई घड़ी का मालिक- PW1 (मृतक के पति) के पास ऐसा कोई मामला नहीं था कि अपीलकर्ता ने उसकी कलाई घड़ी चुरा ली थी - उस संस्करण का मृतक के बच्चों ने भी समर्थन नहीं किया - उनके पास कलाई घड़ी या नकदी की चोरी का कोई मामला नहीं था - अभियोजन अपीलकर्ता के खिलाफ मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा - इसलिए आईपीसी 302/380 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए, अपीलकर्ता ने एक अन्य आरोपी 'आर' के साथ मिलकर एक महिला की गर्दन के चारों ओर कपड़े की एक पट्टी डालकर और फिर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी; और उसके बाद उन्होंने मृतक के घर से एक कलाई घड़ी और कुछ नकदी चुरा ली। सेशन कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302/380/34 के तहत दोषी करार दिया.

अपील में, उच्च न्यायालय ने 'आर' को बरी कर दिया लेकिन अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखा।

इसलिए वर्तमान अपील कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

1.1. मौजूदा मामले में, कोई भी परिस्थिति अपने आप में इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी कि अपीलकर्ता आईपीसी की धारा 302 और 380 के तहत अपराधों का लेखक है। सबूतों के आधार पर, यह मानना बेहद मुश्किल है कि अभियोजन पक्ष ने एक प्रभावी अभियोजन की नींव रखी है और बिना किसी संदेह के साबित कर दिया है कि यह अपीलकर्ता ही है जिसने हत्या की है। यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर ही कायम हुआ है. सभी परिस्थितियों में, श्रृंखला को तोड़े बिना, केवल अभियुक्त और अभियुक्त की संलिप्तता होनी चाहिए। केवल इस आधार पर कि अभियुक्तों को घटना की तारीख की सुबह मृतक के साथ देखा गया था और उन्हें अगले दो दिनों तक उस स्थान पर नहीं देखा गया था, अपने आप में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि यह अपीलकर्ता ही है जिसने घटना लिखी है।

1.2. 'फरार' का अर्थ है, हिरासत से भागने या गिरफ्तारी से बचने के लिए गुप्त रूप से या अवैध रूप से और जल्दबाजी में भाग जाना। सबूतों में यह बात सामने आई है कि आरोपियों ने अन्य लोगों को बताया था कि वे अपने कार्यस्थल गंगटोक से अपने कार्यस्थल पर जा रहे है न्यू जलपाईगुड़ी

में घर. उन्हें घटना के तीसरे दिन न्यू जलपाईगुड़ी में उनके संबंधित घरों से ही हिरासत में ले लिया गया था। इसलिए, यह मानना मुश्किल है कि आरोपी फरार हो गया था। यहां तक कि तर्क के तौर पर यह मान भी लिया जाए कि कथित घटना के बाद उन्हें अपने कार्यस्थल पर नहीं देखा गया, तो भी यह नहीं माना जा सकता कि अपने आप में उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाए।

1.3. यदि हत्या करने का आरोपी का मकसद चोरी था, तो यह समझना फिर से मुश्किल है कि आरोपी ने मृतक द्वारा पहने गए कोई भी गहने क्यों नहीं उतारे। इसलिए, मकसद के संबंध में अभियोजन पक्ष का बयान भी हिल गया है।

1.4. रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य इसके विपरीत यह संकेत देंगे कि चोरी केवल जांच अधिकारी की कहानी है। न तो PW1 जिसकी कलाई घड़ी चोरी होने की बात कही गई है और न ही मृतक के बेटों-PWS 2 और 3 के पास कलाई घड़ी या नकदी की कथित चोरी का कोई मामला है। रिकवरी भी संदिग्ध है. पुनर्प्राप्ति का कोई सुसंगत संस्करण नहीं है. जिस व्यक्ति से वसूली की गई है, अर्थात अपीलकर्ता की मां से पूछताछ नहीं की गई है। अपीलकर्ता की उपलब्धता के बावजूद, वसूली उसकी मां के माध्यम से हुई है। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि वह कैसे देखने को मिली।

1.5. इसमें कोई संदेह नहीं है, केवल दो आरोपी हैं और उन पर आईपीसी की धारा 302/380/34 के तहत आरोप लगाया गया है और उनमें से एक को बरी कर दिया गया है। स्वतंत्र साक्ष्य होने की स्थिति में यह अपने आप में सह-अभियुक्तों को बरी करने का आधार नहीं है। लेकिन ऐसे स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में, आरोपी उस आधार पर सफल हो सकता है।

सुनील कुंडू बनाम झारखंड राज्य 2013 (5) एससीआर 924

(2013) 4 एससीसी 422 और मधु बनाम केरल राज्य 2012 (2) एससीआर 986:(2012) 2 एससीसी 399 - पर भरोसा किया गया।

एस.के. यूसुफ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2011 (8) एससीआर 83: (2011) 11 एससीसी 754; कृष्णा गोविंद पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य 1964 एससीआर 678: एआईआर 1963 एससी 1413; अमृता उर्फ अमृतलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। (2004) 12 एससीसी 224 और राजा बनाम राज्य 2013 (9) एससीआर 230: (2013) 12 एससीसी 674 संदर्भित।

2. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि केवल कलाई सी घड़ी की बरामदगी पर निर्भरता के आधार पर हुई है। यह प्रक्रिया में दोषपूर्ण है और इसके अलावा, यह दी गई परिस्थितियों में अदालत के मन में कोई विश्वास पैदा नहीं करता है, जब बाकी सबूतों के खिलाफ खड़ा किया जाता

है, कि अपीलकर्ता ने चोरी के मकसद से हत्या की है। यह पर्याप्त नहीं है कि डी परिस्थितियाँ अभियुक्त की संलिप्तता की संभावना या संभाव्यता पैदा करती हैं; परिस्थितियों में सारी उंगलियाँ अभियुक्त और अभियुक्त पर ही उठनी चाहिए। इस मामले में वैसी स्थिति नहीं है. परिस्थितियाँ कई अन्य निष्कर्षों को जन्म दे सकती हैं। शृंखला भी ई पूर्ण नहीं है। पहला आरोपी, जो अभियोजन पक्ष के अनुसार आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध का अपराधी है, को बरी कर दिया गया है। राज्य ने बरी किए जाने के ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं की है। यह आईपीसी की धारा 302, 380 सहपठित धारा 34 का मामला है। अभियोजन पक्ष का पूरा सिद्धांत यह है कि यह पहला आरोपी है जिसे उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया है, जिसने मृतक की गर्दन पर कपड़े का टुकड़ा बांध दिया और उसका गला घोंट दिया। अपीलकर्ता के खिलाफ एकमात्र कमजोर सबूत अपीलकर्ता की मां से और उसके माध्यम से पीडब्लू 1 की कलाई घड़ी की बरामदगी है। उसकी जांच नहीं की गई. इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि अपीलकर्ता की उपलब्धता के बावजूद उसकी मां के माध्यम से वसूली कैसे की गई। पुनर्प्राप्ति में लगभग दस दिनों की देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। गवाहों ने प्रकटीकरण बयान या जब्ती का समर्थन नहीं किया है। कलाई के मालिक

पीडब्लू1 के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि अपीलकर्ता ने उसकी कलाई घड़ी चुरा ली हो। वह संस्करण मृतक के बच्चों द्वारा भी समर्थित

नहीं है। उनके पास कलाई घड़ी या नकदी चोरी का कोई मामला नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है और अपीलकर्ता सफल होने का हकदार है। आईपीसी की धारा 302/380 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द किया जाता है।

केस कानून संदर्भ:

2013 (5) एससीआर 924

2011 (8) एससीआर 83

2012 (2) एससीआर 986

1964 एससीआर 678

(2004) 12 एससीसी 224

2013 (9) एससीआर 230

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2004 की आपराधिक अपील संख्या 1010

सिक्किम उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच की आपराधिक अपील संख्या 1 2003 में दिनांक 15.12.2003 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता के लिए आनंद, राजश्री एन. रेड्डी, सुशील बलवाड़ा।

प्रतिवादी की ओर से यूसुफ खान, अरुणा माथुर (अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी के लिए)।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

कुरियन, जे.: 1. अपीलकर्ता गंगटोक में सत्र न्यायाधीश, सिक्किम की फाइल पर 2001 के आपराधिक मामले संख्या 31 में दूसरा आरोपी है। उन पर रंजीत रॉय नामक व्यक्ति के साथ आरोप लगाया गया था

316 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

[2014] 8 एस.सी.आर.

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) (इसके बाद 'आईपीसी' के रूप में संदर्भित) की धारा 34 के साथ पठित धारा 302, 380 के तहत। अभियोजन पक्ष के अनुसार:

"इन दोनों आरोपियों को अपने खर्चों के लिए पहले से ही पैसे की जरूरत थी क्योंकि दुर्गा रॉय (बर्मन) ने अपना काम पूरा करने से पहले ही अपने मालिक सुजीत बसाक से काफी नकदी उधार ले ली थी और कुछ दिनों तक उसके पास अपने मालिक से लेने के लिए कुछ भी नहीं था। पैसे की समस्या मामला तब और गंभीर हो गया जब 5.7.2001 को आरोपी व्यक्ति को रंजीत रॉय के पिता का टेलीफोन आया कि उसकी माँ घर पर गंभीर रूप से बीमार है और उसे तुरंत घर लौट आना चाहिए। उस रात दोनों आरोपी व्यक्ति अपनी वित्तीय समस्याओं के बारे में चर्चा करते हुए देर

तक सोए। अगले दिन (यानि 6.7.2001) सुबह, रंजीत रॉय किराए के कमरे में गए। शिबू बर्मन पहले ही अपनी नौकरी के लिए निकल चुके थे। कुछ देर बाद दुर्गा रॉय (बर्मन) भी कमरे में पहुंचे। दोनों मजबूत स्थिति में थे ऐसा लगा कि ललन प्रसाद के घर में पर्याप्त पैसा था क्योंकि वह लॉटरी के कारोबार में लगा हुआ था और उसके दोनों बेटे भी काम कर रहे थे। इसलिए, दोनों आरोपियों ने ललन प्रसाद के घर से पैसे चुराने की योजना बनाई क्योंकि वह पहले ही नौकरी पर चले गए थे।

शौच के लिए नहाने के साबुन के इस्तेमाल को लेकर आरोपियों की मृतक के बड़े बेटे राजू कुमार से तीखी नोकझोंक हुई थी। 0900 बजे तक दोनों बेटे भी अपने दैनिक कार्यों के लिए निकल गये। तब घर में दोनों आरोपियों के अलावा केवल मृतिका मनोरमा देवी ही बची थी. दोनों आरोपियों ने मृतक मनोरमा देवी के घर से पैसे चुराने के लिए उसे मारने का फैसला किया क्योंकि वह घर में मौजूद एकमात्र व्यक्ति थी। मृतक मनोरमा देवी अपने बेटों के कमरे के अंदर थी जब आरोपी दुर्गा रॉय (बर्मन) ने उससे बात करने का नाटक किया, जिससे उसका ध्यान भटक गया। उसी समय दूसरा आरोपी रंजीत राय अपने कमरे से कपड़े की एक पट्टी लेकर आया और चुपचाप मृत मनोरमा देवी के पीछे चला गया और मौका पाकर आरोपी पर हमला कर दिया.

रंजीत राय ने चुपचाप मृतिका के गले में पट्टी डाल दी और उसका गला दबा दिया. जैसे ही पीड़िता बेहोश हो गई, उसने उसकी गर्दन पर दो बार लिगेचर घेरा और गर्दन के पीछे कसकर गांठ लगा दी, जिसके परिणामस्वरूप लिगेचर द्वारा गला घोंटने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर शव को फर्श पर छोड़कर आरोपियों ने घर की तलाशी ली और एक कलाई घड़ी "सिटको" और नकद 2300/- रुपये ले लिए और पी.ओ. से भाग गए। लगभग 1200 बजे, आरोपी व्यक्तियों को पत्नी श्रीमती काकुले बिस्वास ने देखा। परुसोथम बिस्वास, तेनजिंग और तेनजिंग, गंगटोक से देवराली की ओर जा रहे हैं। आरोपी दुर्गा रॉय, जो उसे जानती थी, ने उसे बताया कि वे घर जा रहे थे। फिर वे कभी गंगटोक वापस नहीं आये।"

2. इस प्रकार अभियोजन पक्ष का यह आगे मामला है कि अपीलकर्ता ने 12.07.2001 को हिरासत में रहते हुए प्रदर्शन पी 6- प्रकटीकरण बयान दिया:

"मेरा सच्चा बयान यह है कि 6/7/01 शुक्रवार को लॉटरी विक्रेता की पत्नी की हत्या के बाद जो घड़ी मैंने चुराई थी, उसे मैंने एनजेपी में रखा है। मैं उक्त घड़ी को पुलिस को सौंप सकता हूं। मैंने कहा है कि वह रख ली है एनजेपी में घरों में देखें।

और

एसडी/-

(अस्पष्ट) अभियुक्त दुर्गा रॉय गवाह

(1) ब्रिज किशोर प्रसाद, पुत्र। राम जनम प्रसाद बसंतपुर पुलिस स्टेशन के पास जिला। सीवान, बिहार, ए/पी। आर.एन. चामलिंग बिल्डिंग एम.जी. मार्ग, गंगटोक, व्यवसाय: लॉटरी एजेंट।

एसडी/-

बृजकिशोर प्रसाद एक्सटेंशनपी-6(ए)

(2) ताशी शेरिंग भूटिया पुत्र। तेनसांग भूटिया - मुझे डर नहीं है (आधिकारिक संगीत वीडियो) तेनसांग भूटिया - मुझे डर नहीं है (आधिकारिक संगीत वीडियो)

एसडी/-एसजे (ई/एन) गंगटोक ए/प्रराज्य सैनिक बोर्ड, पाल्जर स्टेडियम रोड,

गंगटोक व्यवसाय लॉटरी विक्रेता

एसडी/- ताशी एक्सटेंशन.पी6(बी)एसडी/- एसजे (ई/एन)एसडी/- द्वारा रिकॉर्ड किया गया

उदाहरण P6(c) (पीएम राय) एसडी/-पुलिस निरीक्षक एसजे (ई/एन) सदर पी.एस.और गंगटोक"

3. 12.7.2001 को किए गए उपरोक्त खुलासे के आधार पर, अनुलग्नक-पी5 ज्ञापन के अनुसार, घड़ी की वसूली 17.07.2001 को की गई थी। प्रदर्शनी पी6 में दो गवाह जब्ती के भी गवाह हैं। सत्र न्यायालय ने दिनांक 31.12.2002 के फैसले के अनुसार दोनों आरोपियों को धारा 302/380/34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया।

4. अपील में, सिक्किम उच्च न्यायालय ने दिनांक 15.12.2003 के निर्णय द्वारा प्रथम अभियुक्त रंजीत रॉय को जी के लिए निम्नलिखित कारणों से बरी कर दिया:

> "12. इस स्तर पर, यह बताना प्रासंगिक है कि अपीलकर्ताओं पर आईपीसी की धारा 302/34 के तहत आरोप लगाए गए थे और उन्हें इसके तहत दोषी पाया गया है। धारा 34 आईपीसी की सहायता प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक है कि जिस आपराधिक कृत्य के खिलाफ शिकायत की गई थी।
>
> सभी आरोपी व्यक्तियों के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। सामान्य इरादे का तात्पर्य मन की पूर्व बैठक से है। यह किसी स्थान पर अचानक भी बन सकता है। अभियोजन पक्ष ने इस संबंध में कोई सबूत नहीं दिया है।

जहां तक अपीलकर्ता नंबर 1 रंजीत रॉय का सवाल है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिवाय इसके कि घटना की तारीख पर सुबह वह मृतक के घर में मौजूद था और 8 जुलाई, 2001 को गिरफ्तार होने तक फरार रहा। न्यू जलपाईगुड़ी. इसमें कोई संदेह नहीं है कि फरार होने का कृत्य एक प्रासंगिक सबूत है, लेकिन उक्त कृत्य अपने आप में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि वह दोषी है। उसके खिलाफ अपराध से जुड़ने के लिए कोई अन्य अभियोगात्मक सामग्री नहीं है। संदेह चाहे कितना ही प्रबल क्यों न हो, वह प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। उपरोक्त कारणों से, हम यह मानने को इच्छुक हैं कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता नंबर 1 रंजीत रॉय के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं है। इसलिए, वह संदेह के लाभ पर बरी होने का हकदार है।"

(जोर दिया गया)

और

5. हालाँकि, दूसरे आरोपी-अपीलकर्ता के मामले में, अदालत ने इसे इस प्रकार माना:

"13. वर्तमान मामले में, दोनों अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप इस अर्थ में विशिष्ट है कि अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मृतक की हत्या की। अपीलकर्ता नंबर 1 रंजीत रॉय को बरी करने के साथ ही सामान्य इरादे को साझा करने का आरोप लगाया गया विफल रहता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि अपीलकर्ता नंबर 2 दुर्गा रॉय भी बरी हो सकता है। यदि सबूतों के आधार पर यह माना जा सकता है कि वह अपराध का लेखक था, तो मूल प्रावधान के तहत उसे दोषी ठहराने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

इसलिए, आइए हम उसके मामले की अलग से जाँच करें। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, वह घटना दिनांक को सुबह मृतक के घर में पाया गया था। उक्त घर में, नहीं

मृतक को छोड़कर अन्य कैदी मौजूद थे। वह मृतक के एक कमरे के संबंध में शिबू पीडब्लू4 के साथ सह-किरायेदार था। शिबू पीडब्लू4 ने गवाही दी कि वह दोपहर 2.30 बजे मृतक के घर गया था। दोपहर 2.45 बजे तक यह पता लगाने के लिए कि क्या वह अपने कमरे में मौजूद है, लेकिन वह नहीं मिला और उसका कमरा बंद था। वह तब से अपने कमरे में

नहीं लौटा था और 8 जुलाई, 2001 को गिरफ्तार होने तक फरार रहा।

सिटको कलाई को जो दिनांक को गायब पाई गई थी

घटना। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि उसने (अपीलकर्ता संख्या 2 दुर्गा रॉय) मृतक की हत्या करने के बाद कलाई घड़ी प्रदर्शनी IX की चोरी भी की। इसलिए, वह आईपीसी की धारा 302 और 380 के तहत दंडनीय अपराधों का स्पष्ट रूप से दोषी है। सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 302/380/34 आईपीसी के तहत दर्ज की गई सजा को धारा 302 और 380 आईपीसी के तहत एक में बदल दिया गया है।"

(जोर दिया गया)

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील और सिक्किम राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना गया।

7. के विरुद्ध दोषसिद्धि कायम रखने का आधार

यहां अपीलकर्ता जो दूसरा आरोपी है वह है: वह मृतक के घर में था

घटना दिनांक को सुबह.

मृतक के अलावा कोई अन्य कैदी मौजूद नहीं था।

सह-किरायेदार ने बयान दिया था कि जब वह दोपहर 2.30 से 2.45 बजे के बीच मृतक के घर गया था। उसी दिन, उन्हें अपीलकर्ता नहीं मिला और कमरा बंद था।

iv. वह अपने कमरे में वापस नहीं लौटा और वहीं रह गया। 8 जुलाई, 2001 को गिरफ्तार होने तक वह फरार रहा

उन्होंने मृतिका के पति की कलाई घड़ी की बरामदगी दी जो कथित तौर पर घटना की तारीख पर गायब पाई गई थी।

8. इन आधारों पर, यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलकर्ता/आरोपी ने मृतक की हत्या करने के बाद कलाई घड़ी की चोरी भी की और इसलिए, वह आईपीसी की धारा 302 और 380 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी था।

9. हमें डर है, कोई भी परिस्थिति अपने आप में इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी कि अपीलकर्ता आईपीसी की धारा 302 और 380 के तहत अपराधों का लेखक है। यह पीडब्ल्यूएस 3 और 4 के साक्ष्य में है - प्रमुख गवाह कि अपीलकर्ता के अलावा, एक रंजीत रॉय को भी मृतक के घर में देखा गया था और अभियोजन पक्ष के अनुसार, जैसा कि उनकी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, यह रंजीत रॉय-अभियुक्त था नंबर 1 "जिसने चुपचाप मृतिका के गले में कपड़े की पट्टी डाल दी और उसका गला घोंट दिया"। साक्ष्य में यह है कि दोनों आरोपी न्यू जलपाईगुड़ी के थे.

अभियोजन पक्ष का ही मामला है कि पहले अभियुक्त को 5.7.2001 की शाम को संदेश मिला था कि उसकी मां गंभीर रूप से बीमार है और वह घर पर है. पीडब्लू-13 काकुले अभियोजन पक्ष के इस मामले का समर्थन नहीं करती है कि उसने 4 जुलाई, 2001 की दोपहर को आरोपी को सिलीगुड़ी की ओर जाते हुए देखा था। वह उस तारीख के बारे में विशिष्ट और स्पष्ट है क्योंकि यह उसके ससुर की पहली बरसी थी। दरअसल आरोपी फरार नहीं थे. वे अपने मूल स्थान न्यू जलपाईगुड़ी गए थे और उन्हें उनके घरों से ही गिरफ्तार कर लिया गया।

10. एकमात्र अन्य आधार भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद "साक्ष्य अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 27 के तहत उस कलाई घड़ी की वसूली का है, जिस पर अपीलकर्ता द्वारा चोरी होने का आरोप लगाया गया था। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों से, हमें कई कारणों से उस पुनर्प्राप्ति पर भरोसा करना बेहद मुश्किल लगता है। कलाई घड़ी मृतक के पति पीडब्ल्यू 1 की है। पीडब्लूएस 2 और 3 मृतक के बेटे हैं और पीडब्लू1 और मृतक के साथ रह रहे थे। पीडब्लू 1, 2 और 3 के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि कलाई

अपीलार्थी द्वारा पीडब्लू1 की एक घड़ी चोरी कर ली गई थी। हत्या करने के बाद कथित तौर पर आरोपियों द्वारा लिए गए पैसे के बारे में भी उनके पास कोई मामला नहीं है। पीडब्लू 1, 2 और 3 के साक्ष्य में कलाई

घड़ी या नकदी की चोरी के संबंध में कोई फुसफुसाहट भी नहीं है, सिवाय बी के कि कलाई घड़ी की पहचान पीडब्लू1 द्वारा उसकी है। 06.07.2001 से कथित तौर पर कलाई घड़ी के गायब होने या नकदी के नुकसान का कोई संदर्भ भी नहीं है। यह केवल पीडब्लू16-जांच अधिकारी के साक्ष्य में है कि आरोपी का श्रीमती की हत्या के बाद चोरी करने का मकसद था। मनोरमा देवी और पीडब्ल्यू 1 की 2,300/- रुपये की राशि और कलाई घड़ी आरोपी ने ले ली थी। सी

11. एक्ज़िबिट पी5-रिकवरी मेमो में कहा गया है कि कलाई घड़ी अपीलकर्ता की मां द्वारा जांच अधिकारी को सौंपी गई थी। हालाँकि, एक्ज़िबिट पी6-प्रकटीकरण विवरण डी 12.07.2001 को दर्ज किया गया था, जिसे पहले ही ऊपर निकाला जा चुका है, हालांकि, इस तरह से स्वीकार्य नहीं है, जिसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता ने न्यू जलपाईगुड़ी में अपने घर में कलाई घड़ी रखी थी और वह उसे सौंप सकता है। पुलिस। जांच अधिकारी ने पीडब्लू16 के अनुसार जांच की कि कलाई घड़ी अपीलकर्ता के घर से बरामद की गई थी। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलकर्ता की मां के पास वह कलाई घड़ी कैसे आई जिसे अपीलकर्ता ने कथित तौर पर अपने घर में छिपाकर रखा था। उसकी जांच नहीं की गई. एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रकटीकरण विवरण-प्रदर्शनी पी6 एफ घटना के पांच दिन बाद 12.07.2001 को ही दिया गया है और फिर भी वसूली 17.07.2001 को ही प्रभावी हुई है। प्रकटीकरण बयान के साथ-साथ जब्ती

ज्ञापन पीडब्ल्यू 11 और 12 के गवाहों ने अपने साक्ष्य में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके हस्ताक्षर कुछ कागजात पर प्राप्त किए गए थे जिन्हें पुलिस ने पहले ही भर दिया था और अपीलकर्ता द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया था। उनकी उपस्थिति में.

12. मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मृतक द्वारा पहने गए सभी गहने शरीर पर थे और कुछ भी नहीं हटाया गया था। यदि अभियुक्त का मकसद चोरी करना था।

13. जिन साक्ष्यों की हमने ऊपर चर्चा की है, उनके आधार पर हमें यह मानना बेहद मुश्किल लगता है कि अभियोजन ने एक प्रभावी अभियोजन की नींव रखी है और बिना किसी संदेह के यह साबित कर दिया है कि यह अपीलकर्ता ही है जिसने मनोरमा देवी की हत्या की है। यह ध्यान रखना होगा कि यह मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर स्थापित किया गया है। सभी परिस्थितियों में, श्रृंखला को तोड़े बिना, केवल अभियुक्त और अभियुक्त की संलिप्तता होनी चाहिए। केवल इस आधार पर कि अभियुक्तों को घटना की तारीख की सुबह मृतक के साथ देखा गया था और उन्हें अगले दो दिनों तक उस स्थान पर नहीं देखा गया था, अपने आप में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि यह अपीलकर्ता ही है जिसने घटना लिखी है अपराध।

14. 'फरार' का अर्थ है, हिरासत से भागने या गिरफ्तारी से बचने के लिए गुप्त रूप से या अवैध रूप से और जल्दबाजी में भाग जाना। यह साक्ष्य में आया है कि आरोपियों ने दूसरों को बताया था कि वे गंगटोक में अपने कार्यस्थल से न्यू जलपाईगुड़ी में अपने घर तक थे। उन्हें घटना के तीसरे दिन न्यू जलपाईगुड़ी में उनके संबंधित घरों से ही हिरासत में ले लिया गया था। इसलिए, यह मानना मुश्किल है कि आरोपी फरार हो गया था। यहां तक कि तर्क के तौर पर यह मान भी लिया जाए कि कथित घटना के बाद उन्हें अपने कार्यस्थल पर नहीं देखा गया था, तो भी यह नहीं माना जा सकता कि उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जैसा कि सुनील कुंडू बनाम झारखंड राज्य में इस न्यायालय ने माना था। अनुच्छेद-28 को उद्धृत करने के लिए:

"28. यह तर्क दिया गया कि आरोपी फरार थे और इसलिए, उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की जरूरत है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि फरार होना अपने आप में किसी व्यक्ति का अपराध साबित नहीं करता है। कोई व्यक्ति डर के कारण भाग सकता है झूठा फंसाना या गिरफ़्तारी। (देखें: एस.के. युसूफ बनाम स्टेट ऑफ़ डब्ल्यू.बी.2) यह भी सच है कि अन्यत्र छुपने की दलील दी गई है

1. (2013) 4 एससीसी 422। 2. (2011) 11 एससीसी 754।

आरोपी विफल रहा है. उनके द्वारा जांचे गए बचाव पक्ष के गवाहों पर अविश्वास किया गया है। आग्रह किया गया कि इससे प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। हम इस निवेदन को अस्वीकार करते हैं। जब अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं होता है तो वह इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकता है कि आरोपी अपने बचाव की संभावना नहीं बना पाए हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अभियोजन पक्ष को खड़ा होना होगा या अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। यदि उसने उचित संदेह से परे अपना मामला साबित नहीं किया है तो वह आरोपी के मामले की कमजोरी से समर्थन नहीं ले सकता।"

15. यदि मनोरमा देवी की हत्या करने का आरोपी का मकसद चोरी था, तो यह समझना फिर से मुश्किल है कि आरोपी ने मृतक द्वारा पहने गए किसी भी गहने को क्यों नहीं हटाया। इसलिए, डी मकसद के संबंध में अभियोजन पक्ष का संस्करण भी हिल गया है। (कृपया मधु बनाम केरल राज्य में इस न्यायालय का निर्णय देखें)

16. रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य इसके विपरीत यह संकेत देंगे कि चोरी केवल जांच अधिकारी ई की कहानी है। न तो पीडब्लू1 जिसकी कलाई घड़ी चोरी होने की बात कही गई है और न ही मृतक के बेटों-पीडब्ल्यू 2 और 3 के पास कलाई घड़ी या नकदी की कथित चोरी का कोई मामला है।

रिकवरी भी संदिग्ध है. पुनर्प्राप्ति का कोई सुसंगत संस्करण नहीं है. जिस व्यक्ति से वसूली की गई है, अर्थात अपीलकर्ता की एफ मां से पूछताछ नहीं की गई है। अपीलकर्ता की उपलब्धता के बावजूद, वसूली उसकी मां के माध्यम से हुई है। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि वह कैसे देखने को मिली। यह भी कारण हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 31.12.2012 के फैसले में कहा कि "तकनीकी रूप से कहें तो ऐसा नहीं है

धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का अनुपालन। हालांकि कलाई घड़ी Ext. IX को आरोपी दुर्गा रॉय के घर से बरामद किया गया था, लेकिन रिकॉर्ड से पता चलता है कि उक्त कलाई घड़ी आरोपी दुर्गा रॉय की मां ने पुलिस को सौंपी थी।" गौरतलब है कि घर से कलाई घड़ी की बरामदगी

3 (2012) 2 एससीसी 399।

अपीलकर्ता की सजा ही एकमात्र आधार है जिस पर उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है।

17. अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आरोपी नंबर 1 रंजीत रॉय जिस पर गला घोंटने का प्रत्यक्ष कृत्य का आरोप है, उसे उच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है, अपीलकर्ता की सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि मुख्य अभियुक्त के बरी होने से, सामान्य इरादे का पूरा सिद्धांत बिखर गया है और अपीलकर्ता उस आधार पर सफल होने का हकदार है। हमें डर है,

विवाद की सराहना नहीं की जा सकती. इसमें कोई संदेह नहीं है, केवल दो आरोपी हैं और उन पर आईपीसी की धारा 302/380/34 के तहत आरोप लगाया गया है और उनमें से एक को बरी कर दिया गया है। स्वतंत्र साक्ष्य होने की स्थिति में यह अपने आप में सह-अभियुक्तों को बरी करने का आधार नहीं है। बेशक ऐसे स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में, आरोपी उस आधार पर सफल हो सकता है जैसा कि इस न्यायालय ने कृष्ण गोविंद पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य में माना था, जो धारा 302 के साथ पठित धारा 34 आईपीसी का मामला है। उद्धरण के लिए,

> "8.... जबकि इसने अभियुक्त 1, 3 और 4 को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत बरी कर दिया, इसने अभियुक्त 2 को उक्त संहिता की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया। बरी किए गए व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से अपराध। यह कानूनी रूप से असंभव स्थिति है। जब अभियुक्तों को या तो इस आधार पर बरी कर दिया गया कि सबूत स्वीकार्य नहीं थे या उन्हें संदेह का लाभ देकर, कानून में परिणाम वही होगा: इसका मतलब होगा कि उन्होंने अपराध में भाग नहीं लिया। अभियुक्त 1, 3 और 4 के बरी होने का प्रभाव यह है कि उन्होंने हत्या करने में अभियुक्त 2 के साथ मिलकर कार्य नहीं किया। यदि

उन्होंने अभियुक्त 2 के साथ मिलकर कार्य नहीं किया, तो अभियुक्त 2 ऐसा कर सकते थे। उनके साथ मिलकर काम नहीं किया है..."

18. हमारे सामने जो मामला है, उसमें आरोप ये है कि बाद में

4. एआईआर 1963 एससी 1413।

हत्या करने के बाद आरोपी ने चोरी भी की। जैसा कि इस न्यायालय ने अमृता उर्फ अमृतलाल बनाम एमपी5 राज्य के पैराग्राफ-8 में कहा था कि:

"8... एक ही साक्ष्य के आधार पर कुछ अभियुक्तों को बरी कर देने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकल जाता है कि यदि अभियुक्तों को बरी करने और दोषसिद्धि दोनों के संबंध में साक्ष्य की सराहना करते हुए उचित कारण दिए गए हैं तो सभी बरी किए जाने के पात्र हैं। आरोपी...."

19. राजा बनाम सी राज्य मामले में इस न्यायालय द्वारा इसी दृष्टिकोण का अनुसरण किया गया था। पैराग्राफ-12 को उद्धृत करने के लिए:

"12.... यह बताना भी प्रासंगिक है कि उच्च न्यायालय ने सामान्य सिद्धांत पर ध्यान दिया कि यदि अभियोजन का मामला सभी आरोपियों के खिलाफ समान है या उपलब्ध

साक्ष्य के समान सेट पर कुछ आरोपियों के संबंध में है किसी भी आरोपी के संदर्भ में रिकॉर्ड पर, तो न्यायालय सभी आरोपियों को बरी करने में कोई गलती नहीं करेगा और इसके विपरीत, यदि ऐसा करना संभव है, अर्थात् अनाज से भूसी निकालना, तो न्यायालय ऐसा नहीं करेगा। अभियोजन पक्ष के मामले को बनाए रखने में कोई गलती करना जिसके खिलाफ सबूत बरकरार दिखाया गया है।"

20. इस प्रकार, स्वतंत्र साक्ष्य होना चाहिए। अपीलकर्ता की दोषसिद्धि केवल कलाई घड़ी की एफ बरामदगी पर निर्भरता के आधार पर हुई है। हम पहले ही कह चुके हैं कि यह प्रक्रिया में दोषपूर्ण है और इसके अलावा, यह दी गई परिस्थितियों में न्यायालय के मन में कोई विश्वास पैदा नहीं करता है, जब बाकी सबूतों के खिलाफ खड़ा किया जाता है, कि

अपीलार्थी ने चोरी के उद्देश्य से हत्या की। यह पर्याप्त नहीं है कि परिस्थितियाँ अभियुक्त की संलिप्तता की संभावना या संभाव्यता पैदा करें; परिस्थितियों में सारी उंगलियाँ अभियुक्त और अभियुक्त पर ही उठनी चाहिए

5. (2004) 12 एससीसी 224।

एच 6. (2013) 12 एससीसी 674।

इस मामले में वैसी स्थिति नहीं है. परिस्थितियाँ कई अन्य निष्कर्षों को जन्म दे सकती हैं। शृंखला भी पूरी नहीं है. पहला आरोपी, जो

अभियोजन पक्ष के अनुसार आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध का अपराधी है, को बरी कर दिया गया है। राज्य ने बरी किए जाने के ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं की है। यह आईपीसी की धारा 302, 380 सहपठित धारा 34 का मामला है। अभियोजन पक्ष का पूरा सिद्धांत यह है कि यह पहला आरोपी है जिसे उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया है, जिसने मृतक की गर्दन पर कपड़े का टुकड़ा बांध दिया और उसका गला घोंट दिया। अपीलकर्ता के खिलाफ एकमात्र कमजोर सबूत अपीलकर्ता की मां से और उसके माध्यम से पीडब्लू 1 की कलाई घड़ी की बरामदगी है। उसकी जांच नहीं की गई. इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि अपीलकर्ता की उपलब्धता के बावजूद उसकी मां के माध्यम से वसूली कैसे की गई। पुनर्प्राप्ति में लगभग दस दिनों की देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। गवाहों ने प्रकटीकरण बयान या जब्ती का समर्थन नहीं किया है। कलाई घड़ी के मालिक-पीडब्लू1 के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि अपीलकर्ता ने उसकी कलाई घड़ी चुरा ली हो। वह संस्करण मृतक के बच्चों द्वारा भी समर्थित नहीं है। उनके पास कलाई घड़ी या नकदी चोरी का कोई मामला नहीं है।

21. ऐसी परिस्थितियों में, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है और अपीलकर्ता सफल होने का हकदार है। अपील स्वीकार की जाती है. आईपीसी की धारा 302/380 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द किया जाता है। यदि उसे किसी अन्य मामले के संबंध

में हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

अपील की अनुमति.

अनुवादक:- रेशमा खान (यू.आई.डी नम्बर आर.जे-00727)

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक **रेशमा खान** (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।